



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042020-219028
CG-DL-E-09042020-219028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2020/चैत्र 20, 1942

No. 187]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2020/CHAITRA 20, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 245(अ).—केन्द्र सरकार विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नज़रबंदी आदेश फा. सं. 673/35/2015-कस्ट. VIII दिनांक 30.12.2015 के मामले में, ऐसे आंशिक संशोधन से पूर्व किए गए या लोप किए जाने वाले कार्यों के अलावा, खंड 8 (उपर्युक्त) के तहत केवल सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही के प्रयोजन हेतु वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 17 मार्च, 2020 के भारत सरकार की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

- (i) माननीय श्री न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल, मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष
- (ii) माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. आर. मिठा, सदस्य
- (iii) माननीय श्री न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर, सदस्य

2. इस उद्देश्य से यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और उक्त सलाहकार बोर्ड जिसका वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), सा.का.नि. सं. 183 (अ) दिनांक 17 मार्च, 2020 में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा पहले से गठन किया जा चुका है, दिनांक 23 मार्च, 2020 से अन्य मामलों के लिए कार्य करता रहेगा।

[फा. सं. पी.डी.-13004/01/2019-कोफेपोसा]

एस. डी. भसोर, उप सचिव

पाद टिप्पणी : दिनांक 17 मार्च, 2020 की अधिसूचना, सा.का.नि. सं. 183 (अ) को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2020

G.S.R. 245(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in partial modification of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. No. 183(E) dated 17th March, 2020, only for the purpose of the Advisory Board proceedings under Section 8 *ibid*, in the matter of Detention Order F. No. 673/35/2015-Cus.VIII dated 30.12.2015, except as respects things done or omitted to be done before such partial modification, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of :—

- (i) Hon'ble Mr. Justice D. N. Patel, Chief Justice, Chairperson
- (ii) Hon'ble Mr. Justice J. R. Midha, Member
- (iii) Hon'ble Mr. Justice Rajnish Bhatnagar, Member

2. This notification shall come into force with immediate effect for the purpose and the Advisory Board already constituted *vide* Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. No. 183(E) dated 17th March, 2020 shall continue to remain the same for the other matters with effect from 23rd March, 2020.

[F. No. PD-13004/01/2019-COFEPOSA]

S. D. BHASOR, Dy. Secy.

Footnote : The Notification G.S.R. No. 183(E) dated 17th March, 2020 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 17th March, 2020.